डायरी

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

Diary

खंड/VOLUME 30 | संख्या/NUMBER 2

सितंबर / September 2018

केवल निजी प्रचलन के लिए / FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

विशेष अंक / *Special Issue*

एनडीडीबी न्यूज़ मैगज़ीन / NDDB News Magazine

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने डेरी द्वारा

किसानों की आय दोगुनी करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका

पर एनडीडीबी की राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया

श्री राधा मोहन सिंह, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने एनडीडीबी के टी के पटेल सभागार, आणंद में 10 सितंबर 2018 को एनडीडीबी द्वारा आयोजित ''डेरी के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका'' पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।

श्री परषोत्तम रूपाला, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायती राज राज्य मंत्री, भारत सरकार; श्री ईश्वरसिंह ठाकोरभाई पटेल, माननीय सहकारिता, खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन राज्य मंत्री, गुजरात सरकार; श्री लालसिंह वड़ोदिया, माननीय सांसद राज्य सभा; श्री दिलीपभाई पटेल, माननीय सांसद, लोक सभा तथा श्री दिलीप रथ, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

देश के 16 राज्यों के दूध संघों एवं उत्पादक कंपनियों के 600 से अधिक प्रगतिशील डेरी किसान इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेरी फार्म प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी रोकथाम एवं उपचार, पशु प्रजनन में प्रौद्योगिकीय विकास, सहकारिताओं के संचालन में प्रौद्योगिकी की भूमिका, कुशल खाद प्रबंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर विशेषज्ञों द्वारा अभिमुखन सत्र के अलावा, डेरी किसानों को व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी की गई। कुछ महिला किसानों ने बायो गैस प्रौद्योगिकी तथा दूध संकलन में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी, पशु पोषण एवं पशु प्रजनन के बारे में अपने अनुभव साझा किए।

श्री राधा मोहन सिंह ने **पशु आहार के लिए एनडीडीबी के गुणवत्ता चिह्न लोगो** का अनावरण किया। पशु आहार/खनिज मिश्रण पर गुणवत्ता चिह्न अंकित होने पर यह पता चलता है कि विनिर्माता ने मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अपना कर उन्हें क्रियान्वित किया है। निर्धारित मात्रा में खनिज पदार्थों एवं विटामिन से युक्त गुणवत्तापरक आहार खिलाने से डेरी पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार होता है। गुणवत्ता चिह्न अंकित पशु आहार खिलाने के लाभों को प्रदर्शित करने वाले **एनडीडीबी के गुणवत्ता चिह्न लोगो पर बने एक टीवी विज्ञापन** का भी उन्होंने लोकार्पण किया। श्री परषोतम रूपाला ने दूध

एवं दूध उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए **एनडीडीबी द्वारा बनाया गया अन्य टीवी विज्ञापन पियो दूध** का लोकार्पण किया। एनडीडीबी डेरी उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए डेरी उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु उत्पाद, प्रक्रिया एवं पैकेजिंग प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराकर उत्पादों में विविधता लाने में डेरी सहकारिताओं को सहयोग प्रदान करती है और इसके जरिए किसानों की आय में वृद्धि होती है। इसी क्रम में उन्होंने **एनडीडीबी के उत्पाद एवं प्रक्रिया प्रौद्योगिकियां के ब्रोशर** का भी विमोचन किया।

कार्यक्रम के दौरान, नेशनल कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीडीएफआई) के ई-मार्केट प्लेटफार्म का कुशलता पूर्वक उपयोग करके डेरी किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने वाली डेरी सहकारिताओं को भी केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया।

किसानों को संबोधित करते हुए श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों की दीर्घकालिक आजीविका के तौर पर डेरी के विकास में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप, एनडीडीबी डेरी किसानों की प्रौद्योगिकी से संचालित आय प्राप्ति की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। आय प्राप्ति के विभिन्न साधनों पर केंद्रित विविध वैकल्पिक (कृषि एवं संबद्ध) गतिविधियों के जरिए डेरी किसानों को प्रेरित-प्रोत्साहित कर उनमें प्रवृत्त करना उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं कल्याण के लिए आवश्यक है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में समान रूप से वृद्धि हासिल करने के लिए डेरी ग्रामीण भारत की बहुत महत्वपूर्ण विकासात्मक गतिविधि है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने इसे हासिल करने के लिए सात-सूत्रीय रणनीति का लोकार्पण किया है जिनमें शामिल हैं -
i) उत्पादकता वृद्धि ii) सामग्रियों (इनपुट्स) का उचित इस्तेमाल iii) कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना iv) मूल्य वर्धन v) विपणन में सुधार vi) जोखिम को कम करना vii) सहायक गतिविधियों जैसे कि डेरी, मधुमक्खी पालन इत्यादि को बढ़ावा देना। डेरी बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय डेरी योजना चरण-I (एनडीपी-I) और डेरी प्रसंस्करण एवं बुनियादी ढांचा विकास निधि (डीआईडीएफ) के जरिए पहले से ही विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

श्री रूपाला ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए नए प्रयोग जमीनी स्तर पर किसानों के बीच पहुंचने चाहिए। चूंकि हमारी अधिकांश ग्रामीण आबादी युवा है, इसलिए हमें डेरी उद्योग एवं पशुपालन प्रौद्योगिकी से संचालित कुशल आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को प्रचारित-प्रसारित करने की आवश्यकता है। हमारे डेरी क्षेत्र के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिनमें प्रजनन

के क्षेत्र में हुए नए प्रयोगों के जरिए पशु उत्पादकता में सुधार लाना, पोषण एवं पशु स्वास्थ्य तथा दूध उत्पादकों को बाजार की पहुंच उपलब्ध कराना शामिल हैं।

गुजरात के माननीय मंत्रियों ने डेरी सहकारिताओं में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए। उन्होंने डेरी सहकारिताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसरों का सृजन करने का सुझाव दिया।

अपने संबोधन में अध्यक्ष, एनडीडीबी ने डेरी किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने पर केंद्रित एनडीडीबी की नई प्रौद्योगिकी संचालित विभिन्न पहलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एनडीडीबी ने देशी गाय की नस्लों के जिनोमिक चयन के लिए इंडसचिप (INDUSCHIP) नामक एक जिनोटाइपिंग चिप विकसित किया है। इन-विट्रो भ्रूण उत्पादन तकनीक के माध्यम से देशी नस्लों का सुधार भी किया जा सकता है। खाद प्रबंधन को आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाने के लिए एनडीडीबी डेरी किसानों द्वारा फ्लेक्सी बायो गैस संयंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। सोलर पम्प इरिगेटर्स कोऑपरेटिव इंटरप्राइज अर्थात SPICE का निर्माण एनडीडीबी की अन्य महत्वपूर्ण पहल है जिसके जरिए सोलर पम्प अपनाने वाले किसान उत्पन्न अतिरिक्त बिजली की बिक्री कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्होंने यह बताया कि ग्राम स्तरीय डेरी सहकारी समितियों द्वारा साइलेज का उत्पादन और व्यावसायिक तौर पर उनकी बिक्री अन्य पहल है जिसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा चुका है। हरे चारे एवं फसल अवशेषों के भंडारण के लिए इस साइलेज प्रौद्योगिकी में अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। यदि इसे कम लागत वाले चॉपर्स, मोवर्स, बैगर, बेलर और रैपर्स का इस्तेमाल करके 25-50 किलो की बोरियों में पैक किया जाए तो गांव एवं मिल्क शेड में इसको आसानी से बेचा जा सकता है।

श्री रथ ने यह बताया कि एथनो वेटनरी मेडिसीन तकनीकों को लोकप्रिय बनाकर दूध उत्पादक पशु उपचार खर्च में काफी बचत कर सकते हैं जो कि किसानों की आय का एक अप्रत्यक्ष स्रोत बन सकता है। एनडीडीबी की स्वचालित दूध संकलन प्रणाली (एएमसीएस) सॉफ्टवेयर में सहकारी व्यवसाय को मजबूती प्रदान करने के लिए डिजिटल पहल का उपयोग किया गया है। इस एकीकृत सॉफ्टवेयर से डीसीएस स्तर पर संपूर्ण संचालनों में पारदर्शिता आती है और संचालन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एएमसीएस से किसानों के दूध बिल का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाता है।

डेरी किसानों को व्यावहारिक जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी

एनडीडीबी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14 सितंबर 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर 'ख' क्षेत्र में बोर्डों/स्वायत्त निकायों/ट्रस्टों इत्यादि की श्रेणी में राजभाषा हिंदी के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आणंद को वर्ष 2017-18 के लिए राजभाषा कीर्ति के तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से एनडीडीबी के कार्यपालक निदेशक श्री वाय वाय पाटिल को प्रदान किया गया।

Union Minister of Road Transport & Highways launches Giftmilk programme in Nagpur

Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Union Minister of Road Transport & Highways launched NDDB Foundation for Nutrition's (NFN) unique and novel Giftmilk programme at Lal Bahadur Shashtri Hindi Madhyamik School, Hanuman Nagar, Nagpur on 11 August 2018. Shri Chandrashekar Kishanrao Bawankule, Minister of State for Energy, New & Renewable Energy, State Excise, Govt of Maharashtra; Smt Nanda Jichkar, Mayor, Nagpur, Smt Nishatai Sawarkar, President, Zilla Parishad, Nagpur and Shri Dilip Rath, Chairman, NDDB graced the occasion.

NFN has received concurrence of Mother Dairy Fruit and Vegetable Pvt Ltd (MDFVPL) to cover around 6,000 students of 21 schools in Nagpur district under CSR assistance. 200 ml (fortified with vitamin A and D) flavoured milk per day per child will be supplied on all working days. The Bhandara Zilla Dugdh Utpadak Sahakari Sangh, Bhandara will supply milk for the programme.

While launching the programme Shri Gadkari said that children are the foundation for strong and vibrant India. Meeting their nutritional needs in early formative years becomes very important. Malnutrition can be addressed through milk as it is a wholesome food. Regular consumption of milk by children improves their health, cognitive parameters and reduces nutritional deficiencies.

The Union Minister said that NDDB's intervention supported by State Government will go a long way in addressing the livelihood problems and nutritional security in the state and build a better future for the young generation.

In his address, Chairman, NDDB said that malnutrition still remains the major cause of morbidity and mortality among the children in the country. As per the National Health Survey, 2015-16, about 36% of children are undernourished. Maharashtra has a similar scenario with Nagpur having around 33.6% of its children undernourished.

Shri Rath thanked Government of Maharashtra for providing all the support and cooperation for initiating the Giftmilk programme. He requested Shri Gadkari to persuade public sector undertakings to join hands with NFN by allocating their CSR funding so that more children are covered under this programme. Shri Rath urged the Centre/State to have a policy to promote school milk programmes on a countrywide basis targeting children in primary school level by procuring milk from local dairy cooperatives. This will have the twin advantage of improving child nutrition and also alleviating dairy farmers' distress in the country.

NFN has already initiated Giftmilk programme in Gujarat, Jharkhand, Telangana and Tamil Nadu covering around 22,000 children studying in Government schools.

Union Agriculture Minister inaugurates

Bapudham MPC's farmer orientation programme at Champaran

Shri Radha Mohan Singh, Hon'ble Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare, Govt of India inaugurated Bapudham Milk Producer Company's farmer orientation programme at Champaran, Bihar on 8 July 2018 in presence of Shri Dilip Rath, Chairman, National Dairy Development Board (NDDB). The programme was attended by around 1000 milk producers from Champaran.

The event mainly focused on educating the dairy farmers on scientific animal rearing practices for improving productivity of milch animals and encourage them to be a part of producer-centric organisations. The training sessions were facilitated by experts from NDDB, NDDB Dairy Services and NCDFI.

While inaugurating the programme Shri Radha Mohan Singh said that NDDB and its subsidiaries have accepted the challenge of handling livelihood issues of poor dairy farmers in East and West Champaran districts of Bihar.

The Hon'ble Union Agriculture Minister informed that Mother Dairy Fruit and Vegetable Pvt Ltd. (MDFVPL), a wholly owned subsidiary of NDDB brought transparency and fairness in milk procurement operations and marketing practices in the area. Subsequently, another subsidiary of NDDB, NDDB Dairy Services (NDS), organized the farmers and facilitated the incorporation of Bapudham Milk Producer Company (MPC) on 12 April 2017. The MPC started its operation on 2 October, 2017 and presently covers East and West Champaran districts.

In nine months, Bapudham MPC has enrolled more than 17,000 members from about 358 villages and procures around 30,000 Kg milk per day. The MPC has paid about ₹20 crore to its producer members directly in their bank accounts. The MPC has fully automatic village based milk collection system for milk weighment and Fat & SNF testing in presence of farmers. The MPC also has GPRS based real time data transfer system to calculate milk payments and send SMS to farmers. The MPC makes milk payment to farmers directly in their bank accounts in every 10 days cycle.

Shri Dilip Rath said that the Hon'ble Union Agriculture Minister has played a key role in providing market access to the dairy farmers of Champaran and ensuring remunerative returns for milk. Chairman NDDB informed that under National Dairy Plan I, NDDB has approved funding of ₹22 crore to the MPC for implementation of Village Based Milk Procurement Systems. The MPC aims to increase coverage to 1000 villages and procure about 1.60 lakh litre milk per day from around 50,000 milk producers by fifth year.

In February, the Hon'ble Union Minister laid foundation stone for MDFVPL's upcoming modern milk processing plant at Motihari of East Champaran district. The proposed facility will have a capacity of handling 1 lakh litres of milk per day. The MPC has also initiated productivity enhancement services such as Artificial Insemination, Ration Balancing Programme, supply of cattle feed & mineral mixture, fodder development in its operational area. In addition, the MPC is also creating awareness about scientific dairy management practices. Currently, about 358 villages have been covered under productivity enhancement services.

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने श्रेष्ठ डेरी संस्थाओं को एनडीडीबी डेरी इनोवेशन पुरस्कार प्रदान किया

श्री परषोत्तम रूपाला, माननीय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायती राज, भारत सरकार ने एनडीडीबी के टी के पटेल सभागार, आणंद में 1 जून 2018 को विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर देश की श्रेष्ठ डेरी सहकारिताओं को सम्मानित किया। डेरी के जरिए महिला सशक्तिकरण में महिला प्रसार अधिकारियों को भी उनके द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।

उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं के प्रयासों को मान्यता देने तथा उन्हें भविष्य में अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एनडीडीबी ने एनडीडीबी डेरी इनोवेशन पुरस्कार की शुरूआत करने का निर्णय लिया। इस पुरस्कार से बैंचमार्क स्थापित होंगे और संस्थाओं को श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद मिलेगी तथा इससे प्रबंधन उत्कृष्टता, पारदर्शिता, गुणवत्ता उत्पाद, प्रक्रियात्मक सुधार, उत्पादकता वृद्धि, कार्यकुशलता, किसानों को मूल्य, सामाजिक एवं जेंडर समावेश और वित्तीय समावेशन के जरिए अपने व्यावसायिक संचालनों का विस्तार करने हेतु नए तरीकों को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।

श्री ईश्वरसिंह ठाकोरभाई पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सहकार, खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन, गुजरात सरकार, श्री जयद्रथसिंहजी चंद्रसिंहजी परमार, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, पंचायत, पर्यावरण (स्वतंत्र प्रभार), गुजरात सरकार; श्री लाल सिंह वड़ोदिया, माननीय सांसद, राज्य सभा; श्री दिलीपभाई पटेल, माननीय सांसद, लोक सभा तथा श्री दिलीप रथ, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई।

पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री रूपाला ने कहा कि डेरी सहकारिताओं ने डेरी उद्योग की प्रगति में अहम भूमिका अदा की है। हमारे ग्रामीण किसानों ने अपनी आजीविका को बनाए रखने की शक्ति हासिल की है और उपभोक्ताओं को दूध की

आपूर्ति में वृद्धि करने में योगदान दिया है। सहकारिताओं ने किसानों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के साथ उन्हें बाजार की पहुंच उपलब्ध कराई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजीविका की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि उत्पादक स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली डेरी संस्थाएं संगठित क्षेत्र द्वारा हैंडल किए जा रहे दूध के अपने वर्तमान शेयर में वृद्धि करें। इसलिए हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने तथा सहकारिताओं के मूल सिद्धांतों एवं मूल्यों को बरकरार रखने के लिए उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को प्रेरित किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने इस इनोवेशन पुरस्कार की शुरूआत करने के लिए एनडीडीबी की सराहना की। एनडीडीबी के सभी प्रयास हमेशा से ग्रामीण डेरी किसानों के हितों की रक्षा करने पर केंद्रित रहे हैं।

मुख्य अतिथि एवं अन्य सम्मानित अतिथियों ने हमारे देश की श्रेष्ठ डेरी संस्थाओं को इनोवेशन पुरस्कार प्रदान किए। डेरी के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला प्रसार अधिकारियों (एलईओ) को उनके अनुकरणीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। महिला प्रसार अधिकारियों को महिला सशक्तिकरण में उनकी सराहनीय भूमिका के लिए भी सम्मानित किया गया।

गुजरात के माननीय मंत्रियों एवं माननीय सांसदों ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और डेरी सहकारिताओं पर अपने बहुमूल्य विचार साझा भी किए।

पशुपालन निर्देशिका पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री रूपाला ने यह बताया कि डेरी किसानों को बेहतर

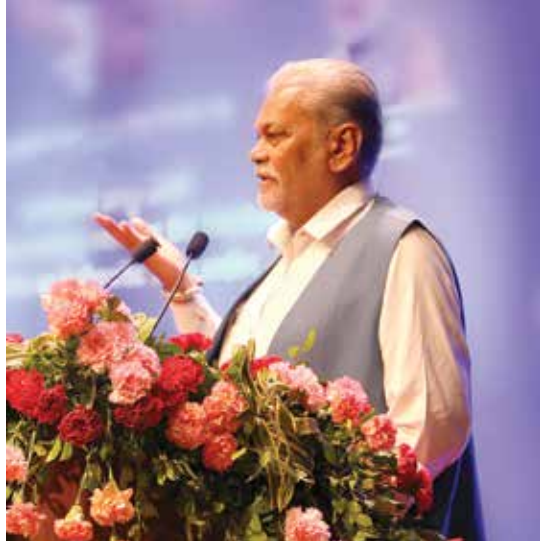

प्रबंधन, पोषण, आहार, चारा एवं स्वास्थ्य संबंधी रोकथाम उपाय के जरिए अपने पशुओं की देख-भाल करने की सुविधा से लैस होने की आवश्यकता है। उन्होंने यह उम्मीद व्यक्त की कि एनडीडीबी के इस प्रकाशन से किसानों को अपने पशुओं के रख-रखाव में मदद मिलेगी। उन्होंने दूध एवं दूध उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देने से संबंधित एनडीडीबी - निर्मित एक टीवी विज्ञापन एवं कृत्रिम गर्भाधान से होने वाले लाभ पर बनी एक फिल्म को भी रिलीज किया।

श्री दिलीप रथ, अध्यक्ष, एनडीडीबी ने कहा कि यह पहला अवसर है जब एनडीडीबी पहली बार डेरी उद्योग और विशेष रूप से उन डेरी सहकारिताओं को सम्मानित कर रही है जो नए प्रयोग करते हैं। श्री रथ ने यह बताया कि एनडीडीबी ने आरंभ से ही डेरी उद्योग में कई नए प्रयोगों में अग्रणी भूमिका निभाई है और यह परम्परा सतत् रूप से जारी है।

उन्होंने किसानों की आजीविका में सुधार लाने पर केंद्रित एनडीडीबी की कुछ नई पहलों को रेखांकित किया - देशी गाय के जीनोटाइपिंग हेतु इंडसचिप; इन-विट्रो भ्रूण उत्पादन प्रौद्योगिकी; थनैला, ब्रूसेलोसिस नियंत्रण परियोजना और आईबीआर टीकाकरण कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन; ग्राम स्तरीय डेरी सहकारी समितियों द्वारा व्यावसायिक स्तर पर साइलेज निर्माण एवं विपणन गतिविधियों का संचालन; डीसीएस द्वारा चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का उपयोग; एनडीडीबी द्वारा शुरू किए गए गुणवत्ता चिह्न के जरिए डेरी सहकारिताओं के गुणवत्ता चिह्न अंकित उत्पाद को बाजार में वैधता दिलाना जिससे विश्व बैंक एवं टाटा ट्रस्ट के सहयोग से शुरू की गई दूध फोर्टिफिकेशन परियोजना के अंतर्गत दूध को विटामिन ए तथा डी से फोर्टिफाई करके सूक्ष्म पोषक तत्वों की कुपोषण संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके; एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन के जरिए शुरू किया गया स्कूल दूध कार्यक्रम जिसमें बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीएसआर निधि का वितरण किया जाएगा; एकीकृत सोलर थर्मल (सीएसटी) प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा देश भर के कई डेरी संयंत्रों को ऊर्जा की लागत में कमी लाने पर लाभ प्राप्ति हो रही है; एनडीडीबी द्वारा विकसित फ्री सोर्स एप्लिकेशन (एएमसीएस) ग्रामीण डेरी सहकारिताओं की मदद कर रहा है और महत्वपूर्ण तरीके से दूध उत्पादकों के निजी बैंक खाते में दूध के बिल का भुगतान सुनिश्चित कर रहा है; सोलर पम्प इरिगेटर्स को-ऑपरेटिव इंटरप्राइज अर्थात स्पाइस का निर्माण; खाद का प्रबंधन - इसका उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करना है, महिलाओं के कठिन श्रम को कम करना है तथा स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप, डेरी किसानों द्वारा विकेंद्रीकृत गैस संयंत्र के इस्तेमाल और मधुमक्खीपालन से संबंधित सशक्तिकरण की गतिविधियों हेतु विभिन्न अनुसंधान किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह बताया कि डेरी किसानों, विशेषकर महिला किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने डेरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में महिला प्रसार अधिकारियों को उनके साहसिक कार्य के लिए बधाई दी।

पशुपालन निर्देशिका पुस्तक का विमोचन

पुरस्कार विजेता

एनडीडीबी डेरी इनोवेशन पुरस्कार

भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, राजस्थान
बी.एम.सी. में जीरो फ्लशिंग कॉसेप्ट के लिए

पंचमहल जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गुजरात
पशु बाजार के लिए

वलसाड जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गुजरात
माईक्रो एटीएम के द्वारा डिजिटल पेमेन्ट के लिए

तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बिहार
शहद के संकलन एवं बिक्री के लिए

एरनाकुलम क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, केरल
मिल्को बाईक के लिए

पुणे जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, महाराष्ट्र
पारंपरिक उपचार पद्धति के लिए

साबरकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, गुजरात
पारंपरिक उपचार पद्धति के प्रसार के लिए

कृष्णा जिला दुग्ध उत्पादक म्युचुअली एडेड सहकारी संघ लिमिटेड, आंध्र प्रदेश
क्राउड फंडिग के लिए

प्रादेशिक सहकारी दुग्ध महासंघ लिमिटेड, उत्तर प्रदेश
दूध एवं दूध उत्पाद में सोया पाउडर की मिलावट की जांच हेतु तकनीक के लिए

कर्नाटक दुग्ध महासंघ लिमिटेड,कर्नाटक
पाउडर ले जाने वाली लाईन के डिजाइन में सुधार के लिए

मांड्या जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, कर्नाटक
घी रेसीड्यू में से फेट की रिकवरी हेतु डिजाइन में सुधार के लिए

बनास जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, गुजरात
ड्युयल परपस वायब्रो हॉट सेक्शन के डिजाइन में सुधार के लिए

कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड,महाराष्ट्र
बछड़ी पालन कार्यक्रम तथा काफ मिल्क रिप्लेसर के लिए

रोपड़ जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, पंजाब
फार्म मशीन के व्यवसायी मॉडल के लिए

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड, मध्य प्रदेश
पनीर अचार के लिए

खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, गुजरात
बायो सीएनजी उत्पादन एवं बॉटलिंग प्लान के लिए

मालाबार क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, केरल
डेरी में आईटी के उपयोग के लिए

श्रीजा महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड, आंध्रप्रदेश
स्वंय सहायता समूह के माध्यम से
बी.एम.सी. की स्थापना के लिए

सुंदरबन सहकारी दुग्ध एवं पशुधन
उत्पादक संघ लिमिटेड, पश्चिम बंगाल
विभिन्न कृषि उत्पादों हेतु बाजार उपलब्ध कराने के लिए

पुरस्कार विजेता (महिला प्रसार अधिकारी)

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लिमिटेड, राजस्थान

लुधियाना जिला दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लिमिटेड, पंजाब

अंबाला जिला दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लिमिटेड, हरियाणा

शाहाबाद जिला दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लिमिटेड, बिहार

बालासुर भद्रक दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लिमिटेड, उड़ीसा

इच्छामती दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लिमिटेड, पश्चिम बंगाल

श्रीजा महिला दुग्ध उत्पादक
कंपनी लिमिटेड, आंध्र प्रदेश

धारवाड़ दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लिमिटेड, कर्नाटक

वेलूर दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लिमिटेड, तमिलनाडु

भरुच जिला दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लिमिटेड, गुजरात

उज्जैन दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लिमिटेड, मध्य प्रदेश

पुणे जिला दुग्ध उत्पादक
सहकारी संघ लिमिटेड, महाराष्ट्र

NDDB to promote dairy farming
in Himachal Pradesh

With a view to promote dairying and rural livelihoods in Himachal Pradesh, Shri Dilip Rath, Chairman, NDDB held wide-ranging discussions with Shri Jai Ram Thakur, Hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh on 8 June 2018 at Shimla. The Hon'ble CM showed keenness to take immediate measures for dairy development in the interest of milk producers. He said that dairy development is not about the commodity called milk but about the socio-economic transformation of rural households in Himachal Pradesh.

Shri Rath said NDDB would provide support to dairy institutions of the State so as to enable them better serve their members and promote producer institutions that remain true to cooperative values.

To address the issue of low milk SNF percentage in dairy animals, NDDB had conducted a study for udder level milk SNF% estimation and impact of feeding balanced ration on milk SNF% level. The study also included other milk quantity & quality along with biological parameters. The main focus was to extend benefits and create awareness among farmers about feeding balanced ration to milch animals.

Chairman, NDDB said that the Dairy Board intends to introduce Ration Balancing Programme in Himachal Pradesh to promote utilization of available feed resources efficiently with value addition. He said that feeding a balanced ration to dairy animals has a significant impact on increasing milk production.

NDDB will support the State Government by making available quality frozen semen doses of indigenous breeds like Sahiwal and Red Sindhi for upgrading nondescript cattle breeds of Himachal Pradesh. NDDB may implement a progeny testing project for Jersey cattle in the identified pockets of the state which would enable production of high genetic merit Jersey bulls to meet the requirement of Jersey bulls by the semen stations across the country.

Palampur semen station of the Animal Husbandry department is located in a crowded residential/ commercial area and has no scope for expansion and strengthening bio-security. NDDB recommends to shift the Palampur semen station to a suitable location where ensuring biosecurity is feasible. NDDB also recommends that Aduwal semen station should be graded. NDDB will provide all technical and managerial assistance in relocating the semen station with complete bio security measures.

डीआईडीएफ के तहत एनडीडीबी को दी गई 440 करोड़ रुपये की पहली किस्त

श्री राधामोहन सिंह, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 10881 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष की शुरुआत की। डेयरी किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए तैयार डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ) के तहत एनडीडीबी को 440 करोड़ रुपये की पहली किस्त दी गई। डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष से 50 हजार गांवों में 95 लाख दूध उत्पादक लाभान्वित होंगे। इस योजना से प्रतिदिन 126 लाख लीटर की अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, 210 टन दूध को सुखाने की दैनिक क्षमता, प्रतिदिन 140 लाख लीटर की दुग्ध अवशीतन क्षमता का सृजन होगा।

Modern frozen semen station
to be set up at Purnea

Shri Nitish Kumar, Chief Minister of Bihar and Shri Radha Mohan Singh, Minister of Agriculture & Farmers Welfare, Govt of India laid the foundation stone of the frozen semen station at Maranga, Purnea on 12 May 2018. Energy Minister Bijendra Prasad Yadav; Animal & Fish Resources Minister Pashupati Kumar Paras; Disaster Management Minister Dinesh Chandra Yadav; Art, Culture & Youth Affairs Minister Krishna Kumar Rishi; National Dairy Development Board Chairman Dilip Rath and Animal & Fish Resources Principal Secretary N Vijayalakshmi were present.

The National Dairy Development Board is helping establish the station. Shri Nitish Kumar said that the frozen semen station would greatly help in boosting the animal husbandry sector in the state as well as eastern part of the country. In his address, the Chief Minister of Bihar stressed the need of Artificial Insemination and hailed it as a major programme for breed improvement. This frozen semen station will play an important role in the proper and timely insemination of cows of indigenous breeds, which would in turn lead to an increase in milk production.

Shri Radha Mohan Singh, Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare said that the frozen semen station is being set up at a cost of ₹64 crore under the Rashtriya Gokul Mission with 100% contribution from the Central Government. Out of this, ₹20 crore has already been released. He said the artificial insemination techniques can increase milk production and productivity. Currently, the artificial insemination is being done by COMFED (Sudha) and its affiliated milk unions in Bihar.

The centre will develop modern bull shed, semen processing lab, feed and godown, agricultural equipment and other facilities. With 300 high genetic merit bulls and production of 50 lakh semen doses per year, this semen station will increase milk productivity of cows and buffaloes in the state. Red Sindhi, Bachaur, Gangatiri, Sahiwal breeds will also be nurtured.

Chairman, NDDB assured that this semen station will be one of the finest semen stations of the country. He highlighted NDDB's efforts in assisting COMFED and its affiliated milk unions in providing a stable cooperative environment for dairying. He emphasized on various interventions through National Dairy Plan in the form of Village Based Milk Procurement System, Ration Balancing Programme and Fodder Development programme being implemented in Bihar with a total outlay of about ₹41 crore.

Shri Rath conveyed that to meet the rising demand of milk the production rate needs to increase. Breed improvement is a simple and effective way to tackle this. Only 14 % of the breedable population in Bihar is covered by AI and rest 86 % is still uncovered. Chairman, NDDB assured that NDDB will ensure timely completion of the project.

Chairman, NDDB met Shri Yogi Adityanath, Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh to present a detailed project report for strengthening dairy cooperatives in Uttar Pradesh.

CM of Jharkhand inaugurates

JMF's cattle feed plant & lays foundation stone for milk products plant in Ranchi

Shri Raghubar Das, Hon'ble Chief Minister of Jharkhand inaugurated NDDB managed Jharkhand Milk Federation's new cattle feed plant and laid the foundation stone for a modern milk products plant in Ranchi on 31 July 2018.

Shri Randhir Singh, Minister for Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries & Cooperation, Govt of Jharkhand; Shri Ram Tahal Choudhary, Member of Parliament, Ranchi; Dr Jitu Charan Ram, Member of Legislative Assembly, Kanke; Shri Dilip Rath, Chairman, NDDB; Shri Sudhir Tripathi, Chief Secretary, Govt of Jharkhand; Ms Pooja Singhal, Secretary, Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries & Cooperation, Govt of Jharkhand and Shri Sangram Chaudhary, Executive Director, NDDB graced the occasion.

While inaugurating the cattle feed plant the Hon'ble CM said that NDDB is putting in best efforts to safeguard interest of dairy farmers in Jharkhand. The state-of-the-art plant has been set up to make Jharkhand self-sufficient in cattle feed manufacturing. The cattle feed plant with a project cost of ₹7.15 crore can manufacture 1500 MT of compound cattle feed pellets in a month. This plant's cattle feed is a rich source of Bypass Protein and 100% free from Urea. It also contains chelated mineral mixture with more bio available macro and micro elements.

Shri Raghubar Das hoped that milk producers of Jharkhand will whole-heartedly accept the cattle feed under brand name Medha Hypro from CFP Hotwar. It will also tackle the nutritional deficiency in cattle and ensure quality milk production.

The CM inaugurated an indigenous cattle farm in Hotwar. The farm has been set up to promote indigenous cattle breeds like Rathi (Rajasthan) and Gir (Gujarat). He also visited a modern fodder demonstration farm with provision to harvest green fodder, both under perennial and seasonal mode for demonstration, like Maize, Bajra, Sorghum, Cowpea, Ricebean, Hybrid Napier, Marvel Grass, Velvet Bean, Augustya, Moringa, Aparajita, Oats, Berseem, fodder beet, Lucerne and Chinese Cabbage etc.

After laying the foundation stone of the milk products plant, the Hon'ble CM said that the increasing demand for Medha milk products has led to the setting up of this new milk products plant. Milk products like Dahi, Paneer, Peda etc can be produced here as per the market needs.

Shri Raghubar Das had launched NDDB Foundation for Nutrition's (NFN) 'Gift Milk' programme for the students of government schools in Latehar last year. Currently, under this programme 17000 students of 43 schools are being provided 200 ml flavoured milk per day per child. While appreciating the effort, the Hon'ble CM announced that the Gift Milk programme will be implemented in other schools

of the state to address malnutrition. Ultimately, about 1,00,000 school children across Jharkhand will be covered under this scheme. Medha Dairy will process, pack and distribute flavoured milk to school children.

Shri Dilip Rath, Chairman, NDDB said that as these initiatives scales up, there would be increased livelihood and employment opportunities, which would eventually help in bringing about rural prosperity in Jharkhand. Chairman, NDDB conveyed that the dairy farmers of Jharkhand are availing the benefits of a transparent milk collection system along with remunerative returns for their produce. On behalf of NDDB, he thanked the Hon'ble CM of Jharkhand and the state administration for providing support and cooperation to enable the Dairy Board to complete projects in record time.

The Jharkhand Milk Federation is currently procuring 1,25,000 litres of milk per day from 2000 villages covering about 16 districts. JMF has paid more than ₹100 crore as milk price to farmers during 2017-18 and the amount is directly being transferred to their bank accounts on regular basis. The Hon'ble CM distributed ₹1.5 crore price difference to dairy farmers. Further, JMF is marketing around 80,000 litres of milk & milk products through approximately 3,000 outlets across Jharkhand.

Apart from milk procurement, processing and marketing, JMF has also taken initiatives towards productivity enhancement of dairy animals through different input activities like providing compound cattle feed & improved fodder seeds and manufacture/supply of chelated mineral mixture etc.

Straw densification & enrichment plant
inaugurated at Hanumangarh

Shri Ajay Singh Kilak, Minister for Gopalan and Cooperation, Government of Rajasthan inaugurated a straw densification and enrichment plant in Hanumangarh, Rajasthan on 23 June in presence of Chairman, NDDB. He also reviewed the Sahiwal PS project in Suratgarh area and interacted with AI technicians and veterinary officers.

NDDB supplied milk & cattle feed worth ₹2 crore

to flood-affected Kerala

NDDB joined hands with the Govt of Kerala and dairy cooperatives in the state to provide relief to the flood affected people of Kerala. The total value of relief material arranged by NDDB was worth ₹2 crore.

More than a million sterile milk packs were distributed among the people lodged in relief camps across the state. These single serve 180 ml packs of toned milk, aseptically packed can be consumed directly without boiling or heating. With a fat content of 3.5% and solids-not-fat (SNF) content of 8.5%, these milk packs are a good source of balanced nutrition. These packs were sourced from the Dakshina Kannada Milk Union's dairy plant in Mangalore.

Dairy farmers in several parts of Kerala were facing an acute shortage of feed and fodder for their milch animals. Inadequate nutrition for the milch animals for even brief periods could adversely affect their health and lead to reduced milk production in the long run. To address this, NDDB arranged supply of 500 MT (10,000 bags of 50 kg each) of cattle feed to the affected areas.

NDDB through its wholly owned subsidiary, Indian Immunologicals Ltd airlifted veterinary medicines worth about ₹5 lakh. Officers of the Dairy Board sourced and distributed relief materials in the state. They worked in close coordination with the officials of the State Government and dairy cooperatives.

Considering the magnitude of the calamity, all NDDB employees have donated a token amount from their salaries for the flood affected people of Kerala.

World Dairy Innovation Award 2018

for new product development

NDDB's Dahi-based spread/dip, an innovative and nutritive product won the World Dairy Innovation Award 2018 in 'Best Children Dairy Product' category at the 12th annual awards ceremony held at the Global Dairy Congress, Warsaw in Poland on June 20, 2018.

The World Dairy Innovation Awards organised by FoodBev Media is the international dairy industry's leading and most established awards scheme; celebrating innovation and excellence across every product category as well as seeking out the best in packaging, marketing, technology and sustainability.

Dahi-based spread/dip is a healthy fun food for children with benefits of fermentation. It can be used as a spread on bread, chapatis and as a dip for biscuits, crackers, nachos etc. It has lower fat and higher protein compared to commercially available margarine, mayonnaise, fat spread, peanut spread, chocolate spread and cheese spread. The product is a suitable vehicle for delivery of probiotics and micronutrients. It doesn't contain preservatives and artificial flavour or colour.

The manufacturing process requires no whey drainage, making the process environment friendly and more amenable to mechanized production.

The product has a shelf-life of 15 days in polypropylene cups stored below 8°C.

Dairy Board inks MoU with OMFED
for setting up modern dairy plant

NDDB signed an MoU with OMFED for setting up a modern five lakh litre capacity dairy plant on 28 April, 2018 at Bhubaneswar in the presence of Shri Naveen Patnaik, Chief Minister of Odisha. The plant has facility to manufacture value added products also.

The State government will provide 51 acres of land and ₹244.74 crore for the project. The newly built automated dairy would have a spray drying milk powder plant of 10 MTPD capacity with manufacturing facility for 40 TLPD curd, 10 TLPD buttermilk, 10 TLPD Lassi, 3.5 TLPD flavoured milk, 3 MTPD Paneer and UHT milk in tetra brick of 1 litre pack in capacity of 60 TLPD.

Shri Dilip Rath Chairman, NDDB along with a team of senior engineers from NDDB and senior OMFED officials visited the dairy site and held discussions for early start and completion of the dairy plant.

Shri Dilip Rath, Chairman, NDDB said that the new dairy plant will serve the twin objective of making

available fresh and pure milk & milk products to the consumers at affordable prices on one hand and provide remunerative prices to producers for their produce on the other.

Aided and supported by NDDB's research, training and professional management services, cooperatives of Odisha will be guided and nurtured to realise their full potential.

CALF receives approval from Export Inspection Council of India

NDDB's CALF has obtained approval from Export Inspection Council of India (EIC) for a wide range of food products like milk & milk products, fruit & vegetable products, infant milk substitute, infant formula, fats & oils, bakery & confectionary, neutraceutical & functional food, water and animal feed etc. It is the only laboratory in Gujarat to cover complete parameters of milk products as per Residue Monitoring Plan (RMP) of Export Inspection Council of India.

This recognition would be beneficial to all EIC approved dairy units to meet their requirement. This would boost NDDB's endeavour to support the dairy & food industry in maintaining high standards for international trade, help industry to serve the farmers and provide safe & good quality products to consumers.

CALF is a multi-disciplinary analytical laboratory of National Dairy Development Board , located at Anand. With state-of-the-art equipment and qualified technical manpower, CALF offers a range of reliable and accurate analytical services. CALF is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) covering chemical, microbiological and animal genetics scope of testing. It is a notified referral laboratory for Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) and recognized by the Bureau of Indian Standards (BIS) for undertaking analysis of various milk and milk products.

NDDB's developmental initiatives
to boost West Bengal's rural economy

Shri Dilip Rath, Chairman, National Dairy Development Board (NDDB) laid the foundation stone for a model DCS building of Chowrangi Women Dairy Cooperative Society (Basanti, South 24 Paraganas district) in presence of Shri Parash Dutta, Chairman, West Bengal Cooperative Milk Producers' Federation Ltd and Shri Anil Verma, Principal Secretary, Animal Resources Development, Govt of West Bengal on 27 July 2018.

The women milk producers of Chowrangi WDCS now believe that dairying is not only a tool for women's liberation, but can also boost up the rural economy. Speaking at the event in Sonarpur's Jaihind auditorium, Shri Rath said that West Bengal needs to diversify from traditional agriculture to dairy farming and allied activities on a large scale.

NDDB plans to adopt this DCS to make it a model dairy cooperative society. The DCS is affiliated to Sundarban Cooperative Milk & Livestock Producers' Union Ltd. Presently, 61 pourer members pours around 104 litres of milk to the society. Apart from milk, Sona mung dal, Dhudheswar rice, Govindobhog Rice, indigenous hen & duck eggs are being procured at Chowrangi DCS.

Keeping in view the role of digital innovation in strengthening cooperative business, NDDB has developed an integrated Automatic Milk Collection System (AMCS) software for dairy cooperatives. On the request of West Bengal Govt, NDDB has installed AMCS software in DCSs affiliated to Sundarban Cooperative Milk & Livestock Producers' Union Ltd. While launching the software, Chairman, NDDB said that apart from introducing transparency in operations, the software will improve process efficiency and provide real time information to dairy cooperatives. AMCS enables milk bill payment directly to farmers' bank accounts. Farmers get instant SMSs for every transaction and have access to all past transactions with AMCS android application.

Focusing on the event theme Sustainable Development through Women Dairy Cooperative, Shri Rath said that dairy cooperatives should come forward to create new opportunities for self-employment in the rural areas. NDDB has been making continuous efforts towards a number of such interventions. It could either be dairy based, agriculture or allied as resources for the same are easily available in rural areas. Experts from NDDB highlighted techniques of ethno veterinary medicine (EVM).

Chairman, NDDB visited the Chowrangi Women DCS at Basanti and interacted with the women milk producers. He also observed EVM demonstration, functional flexi biogas plants and integrated farming system.

Sundarban Cooperative Milk & Livestock Producers' Union Ltd

Since inception in 1997, the Sundarban Cooperative Milk & Livestock Producers' Union Ltd. functioned seasonally for about 4-6 months in a year due to adverse geographical conditions. Deficient dairy infrastructure forced the milk union to stop operations in 2014. In November 2015, with NDDB's

guidance and technical support, the Sundarban Cooperative Milk & Livestock Producers' Union Ltd started its revival plan.

The milk union took up the mission of empowering small and marginal women farmers engaged in dairy/ livestock and agriculture farming in Sundarban. Procurement of almost all agricultural produce of farmers such as milk, indigenous duck & hen eggs, rice, pulses and forest honey were started at DCSs to stop exploitation by middle-men. The union became the first organic milk & livestock union in the country. Availability of quality and hygienic food to the consumers were stressed.

Presently, Sundarban Milk Union, popularly known as Sundarini (South 24 Paraganas district of West Bengal) has 70 Women DCS covering 3500 women farmers with peak milk procurement of over 4000 Kg per day from 7 blocks. The prominent feature of Sundarban Milk Union is that a milk producer has to submit the "Know Your Farmer" (KYF) information (including bank account & identity proof) to become a DCS member. Every milk sample gets tested at DCS level in presence of farmer with acknowledgement slip. 100% payment is done to individual Bank Account of farmers through NEFT in 10 days interval. Sundarini is paying premium price to its farmers and minimum 75% of the consumer rupee is going back to them. Sundarini is now implementing VBMPS under NDP-I (NDDB), NPDD (GoI), Millennium Alliance (FICCI).

The Milk Union initiated extensive campaign for awareness and skill development of farmers on organic and sustainable livestock farming. It has also started the process for organic certification of all Sundarini products. 100% green fodder, Azolla based milk, egg production without using any chemical pesticide or manure is being promoted. Farmers are being advised to use ethno-veterinary medicine and set up herbal garden. The Union stressed on procurement of 100% SS milk cans/milk pails for farmers and marketing of cow ghee, honey in glass bottles only.

During 2017-18, Sundarini has marketed 7 tonnes of honey and has a target of 15 tonnes next year. Organic mangrove forest honey of Sundarban is collected in cooperative mode.

Dairying in West Bengal

In terms of value of output, milk is the single largest agricultural commodity in India. NDDB has been undertaking several initiatives for transforming dairying into an instrument for the development of India's rural people. Today more than 1.66 crore milk producers affiliated to about 1.86 lakh cooperative societies/producer institutions are being benefited from the dairy cooperative movement in the country. West Bengal has always been active participant to the schemes being implemented by NDDB.

Presently, 14 functional milk unions collectively procure about 188 thousand Kg of milk per day from 2,58,000 milk producers covering over 4000 dairy cooperative societies. State's milk production grew at about 2.7 % compared to nation's 4.9 % in last 10 years. As on March 2018, West Bengal's cooperative infrastructure includes 164 BMCs, 12 chilling centres and 11 dairy plants.

Under NDDB's National Dairy Plan I (NDP I), 26 sub projects of 10 End Implementing Agencies (EIAs) are under implementation with the total

grant assistance of ₹43.25 crore. The EIAs are Bhagirathi Milk Union, Paschim Banga Go-Sampad Bikash Sanstha, Icchamati Milk Union, Kishan Milk Union, Kangsaboti Milk Union, Howrah Milk Union, Midnapore Milk Union, Sundarban Milk Union, Kullick Milk Union and Manbhum Milk Union.

The activities being implemented under NDP I in West Bengal include - Strengthening of Haringhata and Salboni Semen Stations to produce 4.81 million high quality disease free semen doses; Bull Production through imported Embryos, Ration Balancing sub projects which would cover 500 villages through Local Resource Persons (LRPs) to provide balanced ration to 35,000 milch animals using locally available feed resources at least cost; under the Fodder Development sub projects, silage making units will be constructed, mowers would be procured for demonstration and bio mass storage silos would be constructed; Village Based Milk procurement System (VBMPS) sub projects would provide fair & transparent milk procurement system to milk producers in 2738 villages, out of which 1256 would be new villages and 53,888 milk producers would be enrolled as members.

किसान कल्याण दिवस समारोह का आयोजन

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने डॉ. कुरियन सभागार में 2 मई 2018 को किसान कल्याण दिवस समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम ग्राम स्वराज अभियान का एक हिस्सा है जिसकी घोषणा अंबेडकर जयंती के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी।

आणंद के डेरी किसानों को संबोधित करते हुए, श्री दिलीप रथ, अध्यक्ष, एनडीडीबी ने कहा की ''में लाखों भूमिहीन, छोटे एवं सीमांत डेरी किसानों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली उत्पादक संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी वजह से हम दूध उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर बन पाए हैं बल्कि विश्व के अग्रणी दूध उत्पादक भी हो सके हैं।'' आज, भारत विश्व दूध उत्पादन में लगभग 20.2% का योगदान दे रहा है और हम पिछले 5 वर्षों से लगातार लगभग 5.7% के वार्षिक दर से वृद्धि कर रहे हैं।

अध्यक्ष, एनडीडीबी ने बताया कि डेरी एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है जो पशुधन क्षेत्र के उत्पादन मूल्य में लगभग 67% का योगदान देती है। डेरी से प्राप्त आय छोटे और सीमांत किसानों के लिए लगभग 25% का योगदान देती है। अत: समान रूप से कृषि में वृद्धि हासिल करने के लिए डेरी विकास ग्रामीण भारत की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विकास गतिविधि है। सीमित संसाधनों, पर्यावरणीय समस्याओं और कम उत्पादकता वाले पशुओं की विशाल पशु आबादी के साथ डेरी मूल्य श्रृंखला में सभी स्तरों पर कार्यकुशलता सुनिश्चित करके ही हम दूध में अपनी आत्मनिर्भरता को निरंतर बरकरार रख सकते हैं और किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं।

यह कार्यक्रम मुख्यत: डेरी की वैज्ञानिक पद्धतियों पर केंद्रित था जिसके चार प्रमुख विषय इस प्रकार थे – फ्लेक्सी बायोगैस संयंत्र अपनाकर खाद का प्रबंधन करना, विभिन्न प्रकार की नस्लों एवं प्रजनक प्रक्रियाओं के जरिए दूध उत्पादन में वृद्धि करना, उचित लागत पर उपयुक्त पशु पोषण प्रक्रियाओं के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करना और रोकथाम संबंधी एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन अपनाकर पशु स्वास्थ्य सुरक्षा की लागत में कमी लाना।

एनडीडीबी राजस्थान में वैकल्पिक गतिविधियों के जरिए
किसानों की आय को बढ़ावा देगी

किसानों की आय को दोगुना करने के भारत सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) राजस्थान में आय में वृद्धि की नई गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। ऐसी गतिविधियां या तो डेरी, कृषि आधारित अथवा संबद्ध गतिविधियां हो सकती हैं क्योंकि इनके लिए संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध होते हैं।

श्री दिलीप रथ, अध्यक्ष, एनडीडीबी ने कहा कि विभिन्न वैकल्पिक गतिविधियों के जरिए दूध उत्पादकों को उनकी आजीविका के अनेक अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित आय प्राप्ति से संबद्ध कई गतिविधियों में शामिल करना उनके आर्थिक उत्थान और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता/स्व-रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए डेरी सहकारी समितियों को आगे आना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण किसानों को मात्र आर्थिक सहायता देने के बजाए उनकी क्षमता निर्माण तथा उन्हें आत्म निर्भर बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। सभी प्रयास ग्रामीण युवाओं को उद्यमी जैसी सोच-समझ रखने के लिए प्रेरित करने वाले होने चाहिएं। एनडीडीबी ऐसी विभिन्न गतिविधियों की दिशा में निरंतर प्रयासरत है जो हमारे दूध उत्पादकों को स्वरोजगार तथा अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान कर सकती हैं। राजस्थान के किसान अब नए विचारों और नई खोज के प्रति काफी उत्सुक हैं और एनडीडीबी इस क्षेत्र की संसाधन क्षमता पर आधारित नई गतिविधियों के जरिए किसानों की आय में वृद्धि हेतु ठोस प्रयास करना चाहती है।

मधुमक्खी पालन: वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को एक स्वतंत्र उद्यम के रूप में विकसित किया जा सकता है और इसमें स्वरोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने की संभावना है। इसके अलावा, यह मुख्य कृषि तथा बागवानी फसलों का पराग के छिड़काव के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। भारत की वर्तमान वनस्पति संपदा में 2000 लाख मधुमक्खी कॉलोनी रखने की क्षमता है जो 215 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है।

एनडीडीबी देश के डेरी नेटवर्क का उपयोग कर किसानों के बीच वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। डेरी सहकारिताओं के पास दूध के संकलन, प्रसंस्करण तथा विपणन की एक सुव्यवस्थित वैल्यू चेन है। इसी प्रकार की वैल्यू चेन शहद के लिए आसानी से स्थापित की जा सकती है। बनासकांठा (गुजरात), सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) तथा मुजफ्फरपुर (बिहार) के दूध संघ अपने डेरी बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करते हुए पहले ही शहद का संकलन तथा विपणन कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन के इच्छुक किसानों के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की सहायता से एक सप्ताह का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है। राजस्थान के दूध संघों को भी किसानों के बीच इस गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए।

खाद प्रबंधन: इसे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनाने और महिलाओं की कठिनाई को कम करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर डेरी किसानों के लिए विकेंद्रीकृत बायोगैस प्लांट स्थापित करने हेतु प्रयास जारी हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व से रखरखाव अच्छा होगा तथा आपस में बांटने की समस्या नहीं

रहेगी, वहीं सामूहिक रूप से संचालन करने पर अतिरिक्त खाद का व्यावसायिक आधार पर निपटान सुनिश्चित होगा। एक बार यह प्रायोगिक परियोजना सफल हो गई, तब गांव स्तर पर सहकारिता नेटवर्क के माध्यम से इसे कम समय में देश भर में दोहराया जा सकता है।

SPICE : एनडीडीबी की एक अन्य प्रमुख पहल Solar Pump Irrigators Cooperative Enterprise अर्थात् SPICE की स्थापना है जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा पम्प के मालिक उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को बेच सकेंगे। एक ओर इससे ऊर्जा कंपनियों का सब्सिडी का भार कम होगा, अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त होगा तथा ट्रांसमिशन एवं वितरण हानि में कमी आएगी, वहीं हमारे उन किसानों को इससे अधिक लाभ होगा, जिन्हें आय का अतिरिक्त स्रोत मिलेगा। किसानों को अतिरिक्त बिजली बेचने का विकल्प देकर प्रोत्साहित करने से वे पानी का अनुकूल उपयोग करेंगे जिसकी डेरी उद्योग की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका है। गुजरात तथा पंजाब में तीन ऐसे प्रयोग पहले से ही चल रहे हैं। राजस्थान में इसको आगे बढ़ाने का कार्य जारी है

साइलेज उत्पादन : गांव स्तरीय डेरी सहकारी समितियों द्वारा साइलेज उत्पादन तथा व्यावसायिक आधार पर इसका विपणन करना एक और पहल है जिस पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा चुका है तथा इसे देश के अन्य भागों में दोहराया जा सकता है। हमारे डेरी पशुओं के लिए वर्षभर, विशेषकर कमी के सीजन में गुणवत्ता पोषक तत्वों तथा मोटे चारे की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरे चारे को साइलेज के रूप में स्टोर करना एक सबसे अच्छा विकल्प है। हरे चारे तथा फसल अवशेषों के भंडारण के लिए साइलेज टेक्नोलॉजी की भारत में बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि एक बार तैयार हो जाने पर इसके भंडारण के लिए कोल्ड चेन तथा चालू खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। यदि इसे कम लागत पर चॉपर, मॉवर, बैगर बेलर तथा रैपर का प्रयोग करके लगभग 50 किलो के बैग में पैक किया जाए तो इसे गांव अथवा मिल्कशेड में आसानी से बेचा जा सकता है।

चारा उत्पादन के लिए गौचर भूमि : इसी प्रकार चारा उत्पादन के लिए डीसीएस द्वारा गौचर भूमि का प्रयोग और इसे सदस्यों को बेचना तथा कमाई को पंचायत के साथ बांटना, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है तथा इसे भी व्यापक रूप से दोहराने की आवश्यकता है।

एथनो वेटनरी मेडिसिन : एथनो वेटनरी मेडिसिन की तकनीक को लोकप्रिय बनाने से दूध उत्पादकों को पशु चिकित्सा लागत में काफी बचत हो सकती है, जो किसानों के लिए आय का एक अप्रत्यक्ष स्रोत बन सकता है। अपनी व्यापक पहुंच तथा किसानों से जुड़ाव के कारण डेरी सहकारिताएं ग्रामीण इलाकों में न केवल इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्षम माध्यम हो सकती हैं, बल्कि ये इन पहलों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध करा सकती हैं।

ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण पर संगोष्ठी

22 जून 2018 को, एनडीडीबी ने जयपुर में ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस समारोह में 1000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि एनडीडीबी उनके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री दिलीप रथ, अध्यक्ष, एनडीडीबी; श्री खेमराज चौधरी, अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, मत्स्यपालन और गौपालन, राजस्थान सरकार; श्री रुपेंग पाटीदार, अध्यक्ष, राजस्थान सहकारी डेरी महासंघ लि.; श्री जाकिर हुसैन, प्रबंध निदेशक, राजस्थान सहकारी डेरी महासंघ लि.; श्री संग्राम चौधरी, कार्यपालक निदेशक, एनडीडीबी और डॉ बी एल सारस्वत, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई।

राजस्थान में डेरी उद्योग

भारत में पशुधन तथा डेरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्पादन मूल्य के संदर्भ में भारत में दूध अकेली सबसे बड़ी कृषि पण्यवस्तु है। एनडीडीबी ने डेरी उद्योग को भारत के ग्रामीण लोगों के विकास का माध्यम बनाने और लाखों छोटे दूध उत्पादकों को डेरी उद्योग के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न पहल आरंभ की हैं। आज देश में डेरी सहकारी आंदोलन के माध्यम से लगभग 1.7 लाख सहकारी समितियों / उत्पादक संगठनों से संबद्ध 1.70 करोड़ से अधिक दूध उत्पादकों को लाभ प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर ये किसान अपने दूध उत्पाद के लिए लगभग ₹4700 करोड़ की राशि मूल्य के रूप में प्राप्त करते हैं। ▶

स्वतंत्रता दिवस समारोह

15 अगस्त, 2018 को 72वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आणंद में श्री दिलीप रथ, अध्यक्ष, एनडीडीबी ने प्रात: 9.00 बजे एनडीडीबी परिसर, आणंद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जिसमें श्री संग्राम चौधरी, कार्यपालक निदेशक तथा एनडीडीबी कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने भव्य परेड का आयोजन किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।

इस सुअवसर पर श्री रथ, अध्यक्ष ने सभी उपस्थित एनडीडीबी कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा – इस अवसर पर हम देश के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और महानुभावों का स्मरण करते हैं, जिनके त्याग एवं बलिदान से हमें आजादी मिली और आज के दिन हम हमारे वीर सैनिकों को सलाम करते हैं जो आज भी देश की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए त्याग और बलिदान दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार, हम आज के दिन उन सभी महानुभावों जैसे कि सरदार बल्लभ भाई पटेल, श्री मोरारजी देसाई, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री त्रिभुवन दास पटेल और डॉ. वर्गीज कुरियन को भी याद करते हैं जिनके विज़न और मार्गदर्शन से डेरी सहकारिता के माध्यम से लाखों किसानों को शोषण से मुक्ति मिली और वे आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बन सके।

अध्यक्ष, एनडीडीबी ने यह जोर देते हुए कहा – हमें इस बात पर गर्व है कि लगभग 73 साल पहले इस क्षेत्र की पहली डेरी सहकारिता के गठन से लेकर आज के दिन तक पश्चिम बंगाल, सुंदरबन के सुदूर क्षेत्र में चौरंगी और हजारों डेरी सहकारिताओं का गठन डेरी बोर्ड के पूर्व कर्मियों और आप सब के कठिन परिश्रम एवं प्रतिबद्धता से ही संभव हो सका है।

आगे उन्होंने यह कहा – मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप सभी के सामूहिक प्रयास और अभिनव सोच तथा सही प्रौद्योगिकी के प्रयोग के परिणामस्वरूप डेरी बोर्ड देश भर में, विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में, डेरी सहकारिताओं को मजबूत बना रहा है और किसानों की आमदनी में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्यरत है। हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि मुजकुवा जैसा गांव स्तर का मॉडल डीसीएस देश भर में फैलाया जाए जिससे किसानों की खुशहाली और ग्रामीण समृद्धि प्राप्त की जा सके और सही मायने में हम गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार कर सकें। अंत में, बोहो नर्सरी के बच्चों को चॉकलेट वितरित किए गए और जलपान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

▶ राजस्थान के ग्रामीण लोग, विशेषकर जो शुष्क तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए पशुपालन एक मुख्य आर्थिक गतिविधि है। राज्य में अक्सर सूखा पड़ता है जिससे अक्सर फसल को नुकसान होता है क्योंकि यहां कृषि बारिश पर आधारित है। ऐसी जलवायु परिस्थिति में डेरी क्षेत्र / डेरी सहकारिताएं बड़ी संख्या में किसानों को वर्ष भर स्थाई आय प्रदान करती रही हैं।

राजस्थान ने एनडीडीबी द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में हमेशा सक्रियता से भाग लिया है। पूर्व में, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत ₹60 करोड़ तथा भावी योजना के अंतर्गत ₹55 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। एनडीपी-। के अंतर्गत कुल ₹223 करोड़ की अनुदान सहायता से 16 अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों की 41 उप परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। एनडीपी-। के अंतर्गत राजस्थान राज्य में लागू की जा रही मुख्य गतिविधियों में राठी, थारपारकर तथा साहीवाल नस्ल के लिए नस्ल विकास कार्यक्रम, बस्सी वीर्य केंद्र को सुदृढ़ करना, चारा विकास कार्यक्रम, राशन संतुलन कार्यक्रम तथा गांव आधारित दूध प्राप्ति प्रणाली जैसी मुख्य गतिविधियाँ शामिल हैं।

वित्तीय सहायता के अलावा, एनडीडीबी डेरी सहकारिताओं को विभिन्न तकनीकी तथा प्रबंधन पहलुओं पर भी सहायता प्रदान करती है। 1992 में राजस्थान सरकार के अनुरोध पर एनडीडीबी ने दूध संकलन, प्रसंस्करण तथा दूध उत्पादों के निर्माण में सुधार करने के लिए आरसीडीएफ तथा इससे संबद्ध दूध संघों का प्रबंधन अपने हाथ में लिया था। 1992 से 2000 की अवधि के दौरान किए गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप आरसीडीएफ तथा इससे संबद्ध दूध संघों का कायापलट हुआ।

संपादन एवं डिजाइनः जन संपर्क एवं संचार विभाग, एनडीडीबी, आणंद 388001
Edited and Designed by PR & Communications Group, NDDB, Anand 388001

facebook.com/NationalDairyDevelopmentBoard

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

NATIONAL DAIRY PLAN
MISSION MILK
THE NEXT REVOLUTION